

कुलवंत सिंह तिवाना और एम. एम. पुंछी से पहले, JJ.BHAWANI DASS,

भवानीदास-याचिकाकर्ता।

बनाम

कौशल्या रानी,- प्रतिवादी

1980 का सिविल संशोधन सं. 1478।

4 दिसंबर, 1980।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)-आदेश 6 नियम 17-बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति में, अभियोक्ता को पूर्व-मुक्ति के लिए एक मुकदमे में गुमराह करने वाले पाठ-प्रतिवादियों में से एक को पक्षकार नहीं बनाया गया ऐसे विक्रेता के खिलाफ सीमा की अवधि समाप्त हो गई है-अभियोक्ता-क्या संशोधन की मांग करके ऐसे विक्रेता को अधिकार के रूप में शामिल करने का हकदार है-ऐसी परिस्थितियों जिनमें ऐसे संशोधनों की अनुमति दी जानी है-बताए गए हैं।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी पक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने की मांग की गई संशोधन वास्तविक गलती और असावधानी के परिणामस्वरूप होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर मांगा गया कि यदि किसी आधिकारिक एजेंसी द्वारा आपूर्ति की गई बिक्री-विलेख की प्रमाणित प्रति में पाठ पर वादि को गुमराह किया जाता है, तो क्या वह, जो भी गलती हो, उसे पूर्व-मुक्ति मुकदमे में अधिकार के रूप में सुधार सकता है, यह बिक्री विलेख की दी गई सत्यापित प्रति में पाठ पर निर्भर करेगा। यदि वादि को प्रदान किए गए दस्तावेजों में पाठ होते जिनसे उसे कोई आभास या संदेह नहीं होता कि उसमें से कुछ गायब है, तो वह अच्छी तरह से यह आश्रय ले सकता था कि उसके द्वारा की गई गलती वास्तविक थी और उसे प्रदान की गई प्रमाणित प्रति द्वारा गुमराह किया गया था। यह फिर से कई अन्य विचारों पर निर्भर करेगा कि क्या न्यायालय वादि को वाद में संशोधन की अनुमति देगा या नहीं। लेकिन, अगर दूसरी ओर, वादि द्वारा प्राप्त प्रमाणित प्रति में पाठ, यह दर्शाते हैं कि वह एक संकेत या सुझाव प्राप्त कर सकता है कि उससे कुछ छूट थी, तो यह वादि का अपने हित में कर्तव्य होगा कि वह मामले को स्पष्ट करवाता। वादि को अपनी आलस्य और उपेक्षा से लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उन परिस्थितियों में वादि को प्रतिलिपि एजेंसी द्वारा की गई त्रुटि को भुनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (पैरा 5)।

श्री जे. के. सुद, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, सिरसा, दिनांक 26 मई, 1980 के न्यायालय के आदेश के संशोधन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 115 के तहत याचिका, आवेदन को खारिज करते हुए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एच. एन. मेहतानी।

प्रतिवादी की ओर से एन. सी. जैन, अधिवक्ता, वी. के. जैन, उनके साथ अधिवक्ता

फैसला

एम. एम. पुंछी, न्यायमूर्ति

(1) यह संशोधन याचिका मेरे विद्वान भाई, के. एस. तिवाना, जे. (जो अब (खुशी से) अब मेरे साथ हैं) द्वारा का वी दिवि पीठ में प्रवेश के लिए आई थी।

एल. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

(1981)2

मेरे साथ) जैसा कि उन्होंने महसूस किया कि इस अदालत के दो एकल पीठ के फैसलों-समी बनाम सिंह बनाम उजागर सिंह, (1) और, गेला राम बनाम कैलाश नाथ और अन्य (2) से स्पष्ट रूप से उत्पन्न होने वाले विचारों के टकराव को हल करने की आवश्यकता है। इस तरह यह याचिका हमारे सामने सूचीबद्ध की गई है।

(2) इसे जन्म देने वाले तथ्य एक संकीर्ण दिशा में हैं। याचिकाकर्ता ने शिकायत में पूरी तरह से विस्तृत कृषि भूमि के एक हिस्से के संबंध में पूर्व-छूट के माध्यम से कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया। अपनी निर्भरता के रूप में, उन्होंने उप-पंजीयक के कार्यालय से प्राप्त पंजीकृत बिक्री विलेख की एक प्रति इसके साथ संलग्न की। उन्हें प्रदान किए गए सी0 पाई में विक्रेता का केवल एक नाम था, जो राधा कृष्ण की पत्नी कौशल्या रानी थी, जो प्रतिवादी थी। मुकदमे के बचाव में, लिखित बयान में यह कहा गया था कि अभियोक्ता ने प्रतिअभियोक्ता-प्रतिअभियोक्ता के सह-विक्रेता को शामिल करने में चूक की थी, जिसने संपत्ति का आधा हिस्सा खरीदा था। आपत्ति उठाए जाने पर, पूर्व-याचिकाकर्ता ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, सिरसा को एक आवेदन दिया, जिसमें मुकदमा में संशोधन करने और राज रानी को मुकदमे में दूसरे प्रतिमुकदमी के रूप में जोड़ने की अनुमति मांगी गई। इस आवेदन को प्रतिवादी के हाथों अभी भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। निचली अदालत ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद 26 मई, 1980 को याचिका को खारिज करने का फैसला किया, यह मानते हुए कि आवेदन की तारीख को मुकदमा समय के साथ वर्जित हो गया था और प्रतिवादी-विक्रेता को एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त हो गया था। इस याचिका में उस आदेश के खिलाफ चुनौती दी गई है।

(3) इस याचिका की सुनवाई के दौरान, हमने रिकॉर्ड बुलाने की आवश्यकता महसूस की। उनके आने पर, हमने केस फाइल और विशेष रूप से पंजीकृत बिक्री-विलेख की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया है, इसके वाचन के एक हिस्से ध्यान देना सार्थक होगा। उसमें यह उल्लेख किया गया है कि यह भूमि कौशल्या रानी पत्नि राधा कृष्ण पुत्र रामदित्तामल निवासी पनजुवाना के पक्ष में समान शेयरों में बेची जा रही थी। बिक्री सम्पूर्ण थी। किला नंबरों (दिए गए खुदरा) में मौके पर जमीन का कब्जा उनके द्वारा विक्रेताओं को दिया गया है।

समीर सिंह बनाम उजागर सिंह, (1 ऊपर) मामले में एस. एस. संधवालिया, जे., (अब मुख्य न्यायाधीश) निम्नानुसार आयोजित किया गया :—

“जैसा कि पहले उजागर किया गया है, वादिगण विक्रेता होने के नाते मूल बिक्री-विलेख वादिगण के कब्जे में नहीं था।

(1) 1976 वर्तमान लॉ जर्नल 463।

(2) 1976 पी. एल. आर. 330

भवानी दास बनाम कौशल्या रानी (एम. एम. पुंचली, जे.)

जो विक्रेताओं के पास था। उन्होंने उक्त बिक्री-विलेख की प्रतिलिपि एजेंसी द्वारा एक प्रमाणित प्रति प्राप्त की थी। वादी उन्हें प्रदान की गई आधिकारिक प्रति की शुद्धता को मानने करने के हकदार थे और इसलिए, उन्होंने उसके अनुसार वादपत्र में खसरा संख्या का उल्लेख किया। ऐसी स्थिति में अभियोक्ता का कर्तव्य यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अपने कब्जे में प्रमाणित प्रति की तुलना मूल से करे जब इसे विक्रेताओं द्वारा दायर किया गया था। यह केवल तब हुआ जब प्रतिवादियों की ओर से विशिष्ट आपत्ति उठाई गई थी कि खसरा संख्या का गलत उल्लेख किया गया था तब मामला वादी के संज्ञान में आया और यह विवाद में नहीं है कि इसके बाद उन्होंने संशोधन के लिए वर्तमान आवेदन को तेजी से आगे बढ़ाया।

(3) यह सर्वविदित है कि वाद के संशोधन के मामले में, प्राथमिक विचार यह है कि क्या इसकी ईमानदारी से मांग की जा रही है और यह भी कि क्या प्रतिवादियों को लागत के साथ पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जा सकता है। प्री-एम्पशन मामलों में यह भी तथ्य के रूप में भी देखा जाना चाहिए कि क्या प्री-एम्प्टर का इरादा पूरी बिक्री को पहले से खाली करना था या अन्यथा। वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभियोक्ता की ईमानदारी संदेह से परे है। उन्होंने किया, और वास्तव में, उन्हें प्रदान की गई आधिकारिक प्रमाणित प्रति की शुद्धता का अनुमान लगाने के हकदार थे। किसी भी वादकारी को आधिकारिक एजेंसी की चूक के लिए पीड़ित नहीं होना पड़ेगा।”

इस दृष्टिकोण, सोढ़ी सिंह और अन्य बनाम बसंत सिंह और एक अन्य, (3), तेजा सिंह और अन्य बनाम भगवान सिंह, (4) और भगवान सिंह और अन्य बनाम कश्मीर सिंह (5) पर भरोसा रखा गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मेहतानी ने इसी तरह के और भी निर्णयों के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने जंग सिंह बनाम बृज लाई और अन्य (6) मामले में “एक्टस क्यूरिएनेमिनेम ग्रेवबिट” सिद्धांत को मान्यता दी थी और यह उनके पक्ष में लागू किए जाने के योग्य है।

(4) ) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने गेलाराम और अन्य बनाम कैलाश नाथ और अन्य, (ऊपर 2),-(3) 1962 पी. एल. आर. 633 पर भरोसा किया।

(5) 1970 पी. एल. आर. 615

(6) 1971 पी. एल. जे 222

(7) 1963 पी. एल. आर 884

न्यायमूर्ति हरबंस लाल, के साथ-साथ जवाला दास और अन्य बनाम गोपाल लाल, (7) द्वारा दिये गए निर्णय में यह तर्क दिया गया है कि सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, किसी मुकदमा के नाम को पूर्व-मुक्ति मुकदमे में शामिल करने की अनुमति न्यायालय द्वारा वाद के संशोधन के माध्यम से नहीं दी जाएगी। गेलाराम के मामले (ऊपर) में समीर सिंह के मामले (ऊपर) में इस प्रकृति के न्यायालय के कुछ निर्णयों पर ध्यान दिया गया था, और इसे इस प्रकार देखा गया था :—

“ऊपर उल्लिखित निर्णयों के बारीकी से अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तों द्वारा भरोसा किया गया है कि यह केवल उन मामलों में है जहां विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह किसी संपत्ति या पूर्व-मुक्ति मामलों में पक्षों के

गलत वर्णन का मामला था कि संशोधन की अनुमति दी गई थी और यह निष्कर्ष निकला कि इस तरह का गलत वर्णन वास्तविक था और अनजाने में किया गया था। जबानी ऐसा कोई मामला उद्धृत नहीं किया गया है जिसमें जवाला दास के मामले (उपरोक्त) में लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लिया गया हो, जिसके तथ्य लगभग वर्तमान में मामले के समान हैं। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई निर्णय नहीं लाया गया है जिसमें शिकायत में संशोधन की अनुमति दी गई हो ताकि उस पक्ष का नाम शामिल किया जा सके जिसे सीमा समाप्त होने के बाद प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में, विक्रेताओं में से एक, अमर डिट्टा का नाम प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की चूक को सद्भावना का कार्य भी नहीं माना जा सकता है। 'सद्भावना' शब्द को सीमा अधिनियम, 1963 की खंड 2 (एच) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:—

“ऐसा कोई भी कार्य सद्भावना से किया गया नहीं माना जायेगा जो उचित सावधानी और ध्यान के साथ नहीं किया गया है।”

यदि वादी-प्रत्यर्थी कैलाश नाथ ने "उचित सावधानी और ध्यान" का उपयोग किया था, तो उन्हें इस बात की जांच कराई गई होगी कि सभी खरीदारों, राम किशन और राम दास के नामों का उल्लेख करने के बाद, "तीन" शब्द (जिसका अर्थ है कि तीन खरीदार) का उल्लेख क्यों किया गया था और उन्हें उप-पंजीयक के कार्यालय से या पटवारियों के कब्जे में मौजूद राजस्व रिकॉर्ड से आसानी से तीन विक्रेताओं के नाम का पता चल जाता।”

(8) 1925 लाहौर 343।

भगवानी दास बनाम कौशल्या रानी (एम. एम. पुंछी, जे.)

(5) इस विषय पर मामले के कानून में जो स्वर्णिम लकीर व्याप्त है, वह इस आशय की है कि एक पक्ष द्वारा अनुमति देने की मांग की गई संशोधन वास्तविक गलती और अनजाने में होने के कारण होना चाहिए। हम समीर सिंह के मामले (ऊपर) और गेला राम (ऊपर) में व्यक्त किए गए विचारों के बीच सुझाए गए विरोधाभास को हल करने से बचेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उत्पन्न होता है, और जो उचित है वह एक संक्षिप्त सार प्रश्न का उत्तर है कि यदि अभियोक्ता किसी आधिकारिक एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए बिक्री-विलेख की प्रमाणित प्रति में पाठ पर भरोसा करता है, तो गुमराह किया जाता है, जो भी गलती हो सकती है, इसे पूर्व-मुक्ति मुकदमे में अधिकार के रूप में सही करें। यहाँ फिर से, यह बिक्री-विलेख की दी गई सत्यापित प्रति में पाठ पर निर्भर करेगा। यदि अभियोक्ता को प्रदान किए गए दस्तावेजों में पाठ होते जिनसे उसे कोई आभास या संदेह नहीं होता कि उसमें से कुछ गायब है, तो वह अच्छी तरह से यह आश्रय ले सकता था कि उसके द्वारा की गई गलती वास्तविक थी और उसे प्रदान की गई प्रमाणित प्रति द्वारा गुमराह किया गया था। यह फिर से कई अन्य विचारों पर निर्भर करेगा कि क्या न्यायालय अभियोक्ता को वाद में संशोधन की अनुमति देगा या नहीं। लेकिन, अगर दूसरी ओर, अभियोक्ता द्वारा प्राप्त प्रमाणित प्रति में पाठ, यह दर्शाते हैं कि वह एक संकेत या सुझाव प्राप्त कर सकता है कि उससे कुछ छूट थी, तो यह अभियोक्ता का अपने हित में कर्तव्य होगा कि वह मामले को स्पष्ट करवाये। अभियोक्ता को अपनी आलस्य और उपेक्षा से लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभियोक्ता को, परिस्थितियों में, प्रतिलिपि एजेंसी द्वारा की गई त्रुटि को भुनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(6) वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, हम पाते हैं कि बिक्री-विलेख की प्रति में दो कोणीय अभिव्यक्तियाँ थीं कि भूमि को समान श्रेणियों में बेचा गया था और कब्जा विक्रेताओं को दिया गया था। यदि इन अभिव्यक्तियों को सावधानी की प्रवृत्ति में पढ़ा जाता है, तो अभियोक्ता को सचेत कर दिया जाता कि एक से अधिक विक्रेता होने की संभावना है और बिक्री-विलेख की प्रमाणित प्रति में उल्लिखित एकमात्र विक्रेता का नाम भ्रामक हो सकता है। यदि अभियोक्ता बिक्री-विलेख के एक विक्रेता के नाम से बुद्धिमान हो जाता है, तो यह सामन्जस्य बिठाना मुश्किल है कि उसमें प्रयुक्त संदिग्ध अभिव्यक्तियाँ उसके ध्यान से बच गई होंगी। वाद 6 जून, 1979 को दायर की गई थी, नकल की अवधि समाप्त होने से शायद ही एक सप्ताह पहले। 4 अप्रैल, 1980 को संशोधन की मांग की गई थी। जब तक संशोधन की मांग की गई, तब तक मुकदमा की सीमा की अवधि समाप्त हो चुकी थी। आपत्ति 8 फरवरी 1980 को लिखित ब्याज में ली गई थी, इसके बावजूद इस प्रकार यह न तो ऐसा मामला है जिसमें संशोधन की मांग की

गई थी कि बिक्री में शामिल संपत्ति के विवरण को हटा दिया जाए या पहले से ही प्रतिवादी के रूप में मुकदमा किए गए पक्ष के नाम के गलत विवरण को स्पष्ट किया जाए। छोड़े गये प्रतिवादी का विवरण आसानी से एकत्र किया जा सकता था यदि बिक्री विलेख के साथ पढ़ा गया था। तो वादी द्वारा तुरन्त इसे उप-पंजीयक के कार्यालय से ठीक किया जा सकता था, या कब्जा या स्वामित्व, या दोनों के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड से विक्रेताओं के नामों को वाद भूमि बारे सत्यापित किया जा सकता था।

(7) उपरोक्त चर्चा के क्रम में हम याचिका में योग्य नहीं पाते हैं। निचली अदालत का आदेश अभेद है। इस प्रकार यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

एन के एस।

इससे पहले आई. एस. तिवाना, जे.

यू. टी. चंडीगढ़, -अपीलार्थी

बनाम

बचना और अन्य, प्रतिवादी

1980 की नियमित प्रथम अपील सं. 154।

8 दिसंबर, 1980।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)-आदेश 41 नियम 22-एक याचिका के साथ एक फ़र्जी तिथि के लिए प्रतिवादी को नोटिस-ऐसी सूचना-चाहे 'अपील की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन' के लिए-प्रति-आपत्ति दायर करने के लिए सीमा की अवधि-क्या ऐसी सूचना प्राप्त होने पर चलने लगती है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 41 नियम 22 को सरसरी नजर से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल एक प्रतिवादी के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई की तारीख तय करने वाले नोटिस की प्राप्ति या सेवा पर है कि प्रति-आपत्ति दायर

करने के लिए उसके खिलाफ 30 दिनों की सीमा की अवधि शुरू हो जाती है। नियम 22 अपील में प्रतिवादी को दो अलग-अलग अधिकार देता है-पहला उन किसी भी आधार पर प्रथम दृष्टांत के न्यायालय की डिक्री को बरकरार रखने का अधिकार है जिस पर उस न्यायालय ने उसके खिलाफ फैसला सुनाया था; और दूसरा अधिकार उस डिक्री पर कोई भी प्रति-आपत्ति लेने का है जिसे प्रतिवादी ने अपील के माध्यम से लिया होगा। पहले मामले में, प्रतिवादी डिक्री का समर्थन करता है और दूसरे में वह उस पर हमला करता है। क्रॉस-ऑब्जेक्शन दाखिल करने का चरण केवल तभी उत्पन्न होता है जब अपील दाखिल की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

*अनुवादक : अनिल कुमार*